भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5389
उत्तर देने की तारीख: 03.04.2025

वन धन विकास योजना के अंतर्गत वन धन केन्द्रों की स्थापना

5389. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण देश में वन धन विकास योजना (वीडीवीवाई) के अंतर्गत स्थापित वन धन केंद्रों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) इन केंद्रों से जुड़े जनजातीय लाभार्थियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) केंद्रों के माध्यम से संसाधित और विपणन की जाने वाली लघु वन उपज (एमएफपी) के प्रकारों का ब्यौरा क्या है;
(घ) जनजातीय समुदायों द्वारा वीडीवीवाई के आरंभ से लेकर अब तक इसके माध्यम से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) जनजातीय उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए किए गए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ङ) "प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)" और प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) की योजनाओं के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से जनजातीय एसएचजी के समूह हैं, जिनका गठन लघु वनोपज (एमएफपी)/गैर-लघु वनोपज (एमएफपी) के मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए किया गया है। वन धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को उनसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित मूल्य संवर्धन गतिविधियों पर व्यय हेतु अधिकतम 15.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) इस योजना को क्रियान्वित (लागू) करने वाली केंद्रीय नोडल एजेंसी है। 28.02.2025 तक, ट्राइफेड ने पीएमजेवीएम और पीएम जनमन योजनाओं के तहत 4,465 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए 60,932.30 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं:
https://trifed.tribal.gov.in/sites/default/files/2025-03/Details%20of%20%20PMJVM%20Van%20Dhan%20Vikas%20Kendras.pdf
इन वन धन विकास केंद्रों ने अब तक (आज की तिथि तक) लगभग 109 करोड़ रुपये की बिक्री की है।
*****